



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3004]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2018 / श्रावण 10, 1940

No. 3004]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2018 / SHRAVANA 10, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3794(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संच्या का.आ. 2993 (अ), तारीख 28 अक्टूबर 2015, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 नवम्बर 2015 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे के डी.एफ.सी. के लिये बी.के.पी.एल. की मुगलसराय और कानपुर के बीच खंड शिफिंग हेतु क्षेत्र-जे (प्रस्थापित पाइपलाईन चैनेज 517.814 से 520.556 तक जिला – कौशाम्बी) में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 06 फरवरी 2016 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विलंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील: सिराथू		जिला : कौशाम्बी		राज्य : उत्तर प्रदेश		
गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल			एक्टेर	वर्ग मीटर
		हेक्टेयर	एक्टेर	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5		
गोविन्दपुर गोरियों	312	00	03	20		
सयारा मीठेपुर	1206	00	04	87		

[फा. सं. आर-25011(11)/247/2017-ओ.आर.-I/ई.-17991]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

S.O. 3794(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2993 (E) dated the 28th October, 2015, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 02nd November 2015; the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the "Shifting of Barauni-Kanpur pipeline between Mughalsarai and Kanpur for DFCCIL of Indian Railway in Part-J (from Existing P/L Ch 517.814 TO 520.556 KM in District-Allahabad) by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 06th February 2016;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: SIRATHU	DISTRICT: KAUSHAMBI	STATE: UTTAR PRADESH		
		Area		
		Hectare	Are	Sq. mt.
1	2	3	4	5
GOVINDPUR GORIYON	312	00	03	20
SAYARA MEETHEPUR	1206	00	04	87

[F. No. R-25011(11)/247/2017-OR-I/E-17991]

PAWAN KUMAR, Under Secy.